सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 16 अंक - 51 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 04 दिसंबर 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता, शिंदे व अजित पवार बनेंगे डिप्टी सीएम

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। देवेन्द्र फ्डणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में वे शपथ लेंगे। बुधवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक निर्मला सीता रमन व विजय रूपाणी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है। देवेंद्र फडणवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तय हो गया है कि वह ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए हैं। उनके साथ अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अध्यक्षता की। विधायक दल की बैठक से बीजेपी के सभी विधायकों ने एक साथ कहा कि वे सभी देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रवि राजा ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूरी पार्टी ने इस फैसले का समर्थन किया है। महाराष्ट्र को आगे की प्रगति के लिए देवेंद्र फ्डणवीस के नेतृत्व की जरूरत है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होते हुए पिछली सरकार में डिप्टी सीएम का पद महाराष्ट्र की जनता की हित के लिए स्वीकारा था।

उपमुख्यमंत्री बनने को राजी शिंदे

हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन फडणवीस को सीएम के रूप में फिर से बहाल करने का फैसला हो गया है। नए सीएम को 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ दिलाई जाएगी। इस फैसले को फडणवीस की लोकप्रियता और प्रशासनिक कौशल के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बारे में पार्टी का मानना है कि चुनावों में महायुति के शानदार प्रदर्शन में इसकी अहम भूमिका रही। एकनाथ शिंदे ने नई महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने पर सहमति जताई है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहली बार नियमों में हुआ बड़ा संशोधन, अधिष्ठाता व अस्पताल अधीक्षक के बढ़े अधिकार

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों की बैठक में लिया निर्णय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में मंगलवार को चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।

इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता

था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था।

प्रबंधकारिणी समिति 2 करोड़ तक करा सकती है काम

इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रुपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।

विष्णु के सुशासन में बेहतर कार्य का प्रयास

नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त किरण कौशल उपस्थित थीं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।

स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन

राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फसामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।

नए नियम से 10 लाख का तक होगा वित्तीय अधिकार

पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रुपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।

आयुष्मान भारत योजना का क्लेम भी बढ़ा

अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।

आधी रात को जेवरा बाजार चौक में युवक की हत्या

- विवाद के बाद नशे में धुत्त नाबालिग ने चाकू से किया नौ वार
- वारदात के आधे घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। आपसी विवाद के बाद जेवरा बाजार चौक में आधी रात को युवक की हत्या हो गई। नशे में धुत्त नाबालिग ने इस हत्या की वारदात को बड़ी बेदर्दी से अंजाम दिया है। आरोपी ने अपने से उम्र में बड़े युवक पर धारदार चाकू से एक नहीं बल्कि पूरे नौ बार वार किया। चाकू लगने से युवक लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो गया। सूचना पर पहुंची जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने हत्या के नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया।

पुलिस के मुताबिक जिसकी हत्या हुई है उसका नाम सागर ठाकुर पिता रमेश ठाकुर (22 साल) है। जबकि आरोपी नाबालिग 15 साल का है। मृतक और आरोपी जेवरा के सतनामी पारा निवासी हैं। इनके बीच पुरानी रंजिश की भी चर्चा है। बताते हैं बीती रात सवा 11 बजे के आसपास सागर ठाकुर और नाबालिग जेवरा बाजार चौक में मिले। इस दौरान नाबालिग नशे में धुत्त होकर सागर ठाकुर को गाली देने लगा। सागर ने मना किया तो भी नाबालिग गाली देता रहा। गुस्से में आकर सागर ने नाबालिग का गला पकड़ लिया और दीवार से टिकाकर दबाने लगा। इस बीच नाबालिग ने अपने जेब से चाकू निकाला और सागर ठाकुर के पेट पर प्रहार कर दिया। चाकू के पहले प्रहार से सागर ठाकुर ढीला पड़ गया तो नाबालिग ने चाकू लगातार नौ प्रहार किया। जिससे सागर ठाकुर लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो गया।

आसपास लोगों को घटना की जानकारी मिलते ही भगदड़ सी मच गई। आधे घंटे के भीतर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया। इधर आज पोस्ट मार्टम के बाद मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी नाबालिग के साथ घटना स्थल पर एक और नाबालिग के मौजूदगी का भी पता पुलिस को चला है। हत्या में उस दूसरे नाबालिग की भूमिका को लेकर फ्लिहाल पुलिस पड़ताल कर रही है।

मृत माता-पिता के नाम से उपसरपंच ने निकाला राशन, गड़बड़ी की शिकायत

ग्रामीणों ने लगाया 18 महीने से राशन निकालने का आरोप

बालोद (एजेंसी)। जिले के नेवारीकला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के उपसरपंच पर मृत मां के नाम से राशन आहरण करने का आरोप लगाया है। ग्राम समिति के लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर के सामने उप सरपंच की शिकायत रखी। वहीं पूरे मामले में खाद्य विभाग ने कहा कि प्रारंभिक दृष्टिकोण में ऑनलाइन चेक करने पर राशन आहरण की बात सामने आ रही है। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। वहीं उपसरपंच ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है।

ग्रामीण अध्यक्ष गणेश राम ने बताया कि ग्राम पंचायत नेवारीकला खाद्यान्न योजना में बड़ा गोल-माल चल रहा है। खुद सैल्स मैन उपसरपंच टिकेश कुमार शर्मा द्वारा अपने मृत मां और पिता के नाम से करीब 18 माह से अपने मृत माता पिता के नाम के राशन का उपयोग स्वयं उपसरपंच टिकेश कुमार शर्मा कर रहा है। वहीं ग्रामीण समिति के सचिव मुनेश कुमार ने बताया कि भाजपा शासन राज्य में आने के बाद नया राशन कार्ड जारी किया गया है।

खुद उपसरपंच द्वारा सचिव और सरपंच से मिलकर अपने नाम से नया राशन कार्ड बना चुका है। सेल्समेन खुद ग्राम पंचायत का उपसरपंच है। बार-बार उनसे सवाल पूछने पर जानकारी न देते हुए गोलमोल जवाब दिया जाता है। जिसके कारण हम कलेक्ट्रेट से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर खाद्य सामाग्री रिकभरी व पद से हटाकर 6 वर्ष के लिए पंचायत में किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं देना बनता है। बाकी आपकी कार्यप्रणाली के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाय।

मामला जब खाद्य विभाग पहुंचा तो जिला अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी जिसके बाद परिणाम चौंकाने वाले रहे उपसरपंच टिकेश शर्मा की स्वर्गवासी मां और पिता के नाम से बने राशन कार्ड से राशन निकाले जाने की बात सामने आई है लेकिन उनके परिवार से किसी के राशन निकलने की बात कही है जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो सदस्य टीम बनाई जाएगी जिसमें खाद्य विभाग और जनपद के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे उन्होंने जांच के बाद ही मामले का स्पष्टीकरण होने की बात की है।

उप सरपंच ने बताया षडयंत्र

गांव के उप सरपंच टिकेश शर्मा ने पूरे मामले को षडयंत्र बताया है उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार सहायता राशि मिलने की उम्मीद में मैं किसी का नाम नहीं कटवाया था इसी दौरान मां की भी मृत्यु हो गई उन्होंने कहा कि 3 महीने से मेरा राशन कार्ड नवीनीकरण हो गया है और मैं राशन नहीं निकल रहा हूं वहीं उन्होंने एक गंभीर मामले का खुलासा किया कि गांव में कई से लोग हैं जो अमृत व्यक्तियों के नाम से राशन कार्ड का आहरण कर रहे हैं अगर जांच होती है तो सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

सुखबीर बादल पर हुआ जानलेवा हमला, पकड़ा गया आरोपी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला किया गया है। स्वर्ण मंदिर में उन पर गोली चलाई गई है, हालांकि वे सही सलामत हैं। वे अकाल तख्त साहिब की तरफसे दी गई धार्मिक सजा भुगतने हरमंदिर साहिब पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को गिरफ्तार कर लिया है।

सूत्रों के अनुसार, हमलावर नारायण सिंह चौड़ा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी रहा है। चौड़ा 1984 में पाकिस्तान गया था और आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी में मददगार रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए उसने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध और देशद्रोही साहित्य पर एक किताब भी लिखी है। वह बुड़ैल जेलब्रेक मामले में भी आरोपी है। नारायण इससे पहले पंजाब की जेल में सजा काट चुका है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे सुखबीर सिंह बादल घंटाघर की तरफ हरमंदिर साहिब के गेट के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक शख्स आया और उसने जेब से पिस्तौल से गोली चला दी जो सुखबीर बादल के पास से गुजरते हुए दीवार पर जा लगी। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को घेरा डाल लिया और आरोपी को भी पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। गेट पर दूसरी तरफ सुखदेव सिंह ढींडसा भी तैनात थे। वहीं दरबार साहिब में गोली चलने की आवाज से संगत में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी मंगलवार को भी श्री हरमंदिर साहिब में घूमता देखा गया था। वहीं खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट थी और उस पर नजर रख रही थी। अकाली नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सुखबीर बादल की सुरक्षा में कोताही बरती है। वहीं एडीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुखबीर बादल को उचित सुरक्षा दी गई थी। हमलावर कल भी यहां था। आज भी उसने सबसे पहले गुरु जी को नमन किया। गोली किसी को नहीं लगी है।

ये क्या सिखाएंगे बच्चों को सदाचार

श्रीकंचनपथ

रायपुर जिले के परसदा गांव का एक हेडमास्टर अभनपुर स्थित बीईओ ऑफिस पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना बढ़िया सीआर दर्ज कराने के लिए बीईओ पर दबाव बनाया। ऊंची आवाज में बोलते हुए अपनी फाइल बीईओ के आगे पटकी। इसके बाद बीईओ ने फाइल को उठाया और उसे वापस हेडमास्टर के आगे पटक दिया। हेडमास्टर तैश में आ गया और फाइल को उठाकर उससे बीईओ पर हमला कर दिया। महिला बीईओ भी गुस्से में आ गईं और उठकर हेडमास्टर से हाथापाई करने लगी। इस द्वंद्व में हेडमास्टर भारी पड़ गया और उसने महिला बीईओ को टेबल पर पटककर उसका गला दबा दिया। बीच बचाव कर लोगों ने हेडमास्टर को बाहर निकाला। विभाग ने हेडमास्टर को निलंबित कर दिया। वहीं एफआईआर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विवाद ने इसलिए तूल पकड़ लिया क्योंकि बीईओ महिला थी। वैसे इस तरह के झगड़े और फाइलों की पटका-पटकी दफ्तरों में होती रहती हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस सिस्टम में हेडमास्टर और बीईओ जैसे अधिकारी ही अपना आपा खो देते हों, उस सिस्टम पर कितना भरोसा किया जा सकता है? शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र बनता-बिगड़ता है। इसलिए शिक्षा पर खूब जोर दिया जाता है। पर अब शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां हासिल करना रह गया है। इसी से अर्हता बनती है और लोग विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं। 1970-80 के दशक तक अधिकांश परिवारों के पास साइकिलें हुआ करती थीं। जब घर में पहला वाहन आता तो बच्चों को वाहन चलाना पिता ही सिखाया करते थे। मोड़ और क्रास-रोड पर गाड़ी धीरे करना, हार्न देना, सड़क के बायीं ओर चलना, गति नियंत्रित रखा जैसे सुरक्षा नियम पिता ही अपने बच्चों को सिखाते थे। बच्चा अपना होता था, इसलिए उसकी सुरक्षा की चिंता होती थी। उस पीढ़ी के लोग अब भी यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। फिर आया ड्राइविंग स्कूलों का दौर। इसके साथ ही आ गई आरटीओ एजेंट्स की बाढ़। भले ही ड्राइविंग कौशल का टेस्ट लिया जा सकता हो पर सिस्टम के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि लाइसेंसधारी अपने कौशल का कैसा इस्तेमाल सड़क पर करेगा। उसका काम तो लाइसेंस जारी करने के साथ ही खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही स्कूल, कालेज की पढ़ाई के साथ भी है। यहां बच्चे शिक्षित तो होते हैं पर इस ज्ञान का करना क्या है इसे सुनिश्चित करने का कोई तंत्र अभी विकसित नहीं किया जा सका है। शिक्षा से संस्कारों के इस लोप के दर्शन हर जगह किये जा सकते हैं। मंच और दर्शकों के बीच से लगातार आना जाना, अपने स्थान पर खड़े हो जाना, तिराहों और चौराहों पर भीड़ लगाना, बीच सड़क गाड़ी रोककर बातें करना, ओवरटेकिंग के लिए सड़क को पूरी तरह घेर लेना इसी संस्कारहीनता को दर्शाता है। शिक्षा बताती है कि यह गलत है पर संस्कार के बिना इसपर अमल संभव नहीं।

संपादकीय

महिलाएं जीत की गारंटी बनीं

"हमारे देश की महिलाओं का मिजाज अलग है। वे खुद से ज्यादा परिवार के बारे में सोचती हैं। यही वजह है कि वे जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषायी जंजालों में पड़े बिना सिर्फ उस पार्टी या नेता को चुनती हैं, जो उनके भले की बात करता है। अपने स्वार्थ से ही सही, पर क्या आपको लगता है कि हमारे राजनेता जन-कल्याण में पर्याप्त ध्यान नहीं लगाते? वे चुनाव के समय सामाजिक दरारों को चौड़ा कर वोट जुटाते हैं और फिर उस वोट बैंक को बिसरा देते हैं? एक लोकप्रिय शोशा यह भी है कि राजनीति जन समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया बन चुकी है?

इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको पिछले साल, यानी 2023 में वापस ले चलना चाहता हूं। उन दिनों मध्य प्रदेश में सत्ता-विरोधी लहर आसमान छू रही थी। उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक 'लाडली बहना योजना' की शुरुआत की और सारी 'एंटी इनकंबेंसी' हवा हो गई। वह तीसरी बार चुन लिए गए। यह बात अलग है कि भाजपा ने उनकी जगह भोपाल में नए नेतृत्व को मौका देना बेहतर समझा। इसके पहले हुए हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों में भी कांग्रेस सिर्फ इसलिए वापसी कर सकी, क्योंकि उसने महिलाओं के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का वायदा किया था।

चुनावी लड़ाइयों में अमोघ अस्त्र बन चुकी इन योजनाओं को वर्ष 2001 के तमिलनाडु चुनावों में जयललिता जयराम ने शुरू किया था। महिलाओं पर चले गए इस दांव से चेन्नई के सत्ता-सदन में उनकी जबरदस्त वापसी हुई थी। उनके बाद नीतीश कुमार ने इस जादुई मंत्र को आत्मसात किया। साल 2006 में उनकी सरकार ने फैसला किया कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। बिहार को जानने वाले जानते हैं कि वहां बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। छोटी बच्चियों को प्राइमरी स्कूल के बाद आस-पास के गांवों में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाना पड़ता है। अक्सर उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, क्योंकि घर में किसी सदस्य के पास प्रतिदिन उन्हें दूसरे गांव ले जाने और लाने की फुरसत नहीं होती थी।

इस पुराने सिलसिले ने महिलाओं को पीछे धकेल दिया था। सरकार से मिली साइकिल ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। मैंने खुद बिहार की सड़कों पर दर्जनों बच्चियों को खिलखिलाते हुए साइकिल पर स्कूल आते-जाते देखा है। वे पढ़ रही थीं, खुली हवा में सांस ले रही थीं और अपने अंदर इस विश्वास को संजो रही थीं कि वे एक नए बिहार की संरचना करेंगी। साइकिल योजना के लागू होने से पहले और बाद के बिहार में यदि सरकारी कार्यालयों में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात, शिक्षा दर और अन्य सामाजिक पैमानों पर आप स्त्रियों की भागीदारी आंकें, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे।

सन् 2010 के चुनाव में बिहारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। चुनाव आयोग के आंकड़े गवाह हैं कि 51.12 प्रतिशत पुरुषों ने और 54.49 फीसदी महिलाओं ने वोट डाले। बिहार के सामाजिक समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता की सीढ़ी बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। नीतीश कुमार अकेले सत्ता हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनके बिना ये दोनों पार्टियां भी हुकूमत में आने की स्थिति में नहीं हैं। इसी का नतीजा है कि एक छोटे अंतराल को छोड़ नीतीश कुमार तो 19 वर्षों से 1, अणे मार्ग पर काबिज हैं। अप्रैल 2016 में शराबबंदी का निर्णय कर वह आधी आबादी के और अधिक दुलारे बन चुके हैं।

पटना के इन शुरुआती प्रयोगों के बाद पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में तमाम पार्टियों ने महिलाओं के हक में अनेक फैसले किए। मौजूदा चुनाव परिणाम इसका उदाहरण है कि किस तरह महिलाओं की भागीदारी सत्ताओं को उखाड़ सकती है या पुरानी सरकार को दोबारा जमे रहने के लिए खाद-पानी मुहैया करा सकती है। हरियाणा में हवा कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प-पत्र में लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा की। इसके तहत हर महीने महिलाओं को 2,100 रुपये मिलेंगे। साथ-साथ अव्वल बालिका योजना के तहत कॉलेज जाने वाली हर ग्रामीण लड़की को स्कूटी मुहैया कराने का वायदा किया गया। यही नहीं, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया। नतीजतन, सारी सत्ता विरोधी लहर हवा हो गई और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड में भी यही हुआ। शिंदे सरकार की लाडकी बहिण योजना और हेमंत सोरेन की मंइयां सम्मान योजना ने महिलाओं को लामबंद करने में जबरदस्त भूमिका अदा की। दोनों सत्ता बचाने में कामयाब रहे।

हमारे देश की महिलाओं का मिजाज अलग है। वे खुद से ज्यादा परिवार के बारे में सोचती हैं। यही वजह है कि वे जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषायी जंजालों में पड़े बिना सिर्फ उस पार्टी या नेता को चुनती हैं, जो उनके भले की बात करता है। अपने स्वार्थ से ही सही, पर भारतीय राजनीति शताब्दियों से पीछे धकेली गई महिलाओं को आगे लाने का नेक काम कर रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है।

यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं पर नजर डालनी जरूरी है। कोरोना के वक्त से शुरू हुई 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' ने गरीबों के एक बड़े वर्ग को न केवल जिंदा रखा, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। यह सर्वविदित है कि जब पेट भर जाता है, तो कोई भी अपने परिवार की बेहतरी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता है। एक बार अन्न संबंधी चिंता से मुक्त होने के बाद देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करना शुरू किया। इससे न केवल उनका जीवन बदला, बल्कि देश के जीडीपी में भी सुधार आया। इसी तरह, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय योजना ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को बुलंद किया। केंद्र सरकार अब तक महिलाओं को 11.6 करोड़ निजी शौचालय मुहैया करा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भी देश भर की 10.27 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

यह लाभार्थी वर्ग एक नए सियासी और सामाजिक समुदाय के तौर पर उभरा है। जान लें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू इन कार्यक्रमों का वैसा ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जैसा कभी दलितों-पिछड़ों के आरक्षण, शारदा ऐक्ट अथवा सती प्रथा उन्मूलन कानून ने किया था। आप पूछ सकते हैं कि यदि यह दांव इतना कारगर है, तो हमारे राजनीतिज्ञ समाज बांटने के नारे क्यों लगाते हैं? इस थोथी नारेबाजी के स्थान पर अगर सियासी सूरमा अपना रिपोर्ट-कार्ड लेकर जनता के समक्ष हों, तो भारतीय मतदाता उन्हें निराश नहीं करेंगे। ये योजनाएं 'मंडल और कमंडल' से अधिक कारगर और कल्याणकारी हैं, लेकिन हमारी 'माननीय' बिरादरी आदत से मजबूर है। हालांकि, इस मुद्दे का स्याह पहलू भी है। मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी निर्णायक तौर पर भले बढ़ रही हो, पर सत्ता-सदनों में उनकी संख्या अभी तक नाकाफी है। उम्मीद है, हमारे नेता इस ओर भी नजर डालने का कष्ट करेंगे।

नजरिया

भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल होना ही होगा

भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी हैं।

प्रहलाद सबनानी

देश की अर्थव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है।

भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यत: देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

उक्तवर्णित विभिन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकडें वर्ष 2021-22 तक के हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिती लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यत: निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्स स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास यात्रा अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा।

सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मोडेल के कई लाभ हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की स्कीम बहुत पुरानी हैं एवं समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सका है। जबकि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप ही बदल गया है। ग्रामीण इलाकों में अब केवल 35 प्रतिशत आय कृषि आधारित कार्य से होती है शेष 65 प्रतिशत आय गैर कृषि आधारित कार्यों से होती है। अत: ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे इन बैकों को अब नए व्यवसाय माडल खड़े करने होंगे। अब केवल कृषि व्यवसाय आधारित ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है।

भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग ही, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी भाग, मध्य भाग, उत्तर-पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बड़ी जनसंख्या को डेयरी उद्योग से ही सबसे अधिक आय हो रही है। अत: देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। केवल दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। डेयरी उद्योग को अब पेशेवर बनाने का समय आ गया है। गाय एवं भैंस को चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, आदि समस्याओं का हल भी खोजा जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करनी होगी। इससे खाद्य सामग्री की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उत्पादन उचित रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी अब समय की मांग बन गया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। अत: इन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकानों को बनाने के काम को गति दी जा सकती है। देश में आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंजूमर सहकारी समितियों का भी अभाव है। पहिले इस तरह के संस्थानों द्वारा देश में अच्छा कार्य किया गया है। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या को भी हल किया जा सकता है।

देश में व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से ईज आफडूइंग बिजिनेस के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके। सहकारी संस्थानों को पूंजी की कमी नहीं हो इस हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ऋण के ऊपर अत्यधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है। सहकारी क्षेत्र के संस्थान भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकें ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं।

विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र में लागू किए गए कानून बहुत पुराने हैं। अब, आज के समय के अनुसार इन कानूनो में परिवर्तन करने का समय आ गया है। सहकारी क्षेत्र में पेशेवर लोगों की भी कमी है, पेशेवर लोग इस क्षेत्र में टिकते ही नहीं हैं। डेयरी क्षेत्र इसका एक जीता जागता प्रमाण है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नए मंत्रालय का गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए के सहकारी क्षेत्र में भी पेशेवर लोग आकर्षित होने लगेंगे और इस क्षेत्र को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे। साथ ही, किन्हीं समस्याओं एवं कारणों के चलते जो सहकारी समितियां निष्क्रिय होकर बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं, उन्हें अब पुन: चालू हालत में लाया जा सकेगा। अमूल की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों द्वारा सफलता की कहानियां लिखी जाएंगी ऐसी आशा की जा रही है। सहकारिता से विकास का मंत्र पूरे भारत में सफलता पूर्वक लागू होने से गरीब किसान और लघु व्यवसायी बड़ी संख्या में सशक्त हो जाएंगे।

(ये लेखक के विचार हैं)

व्यवस्था में पारदर्शिता से दूर होगा कुपोषण

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनामिक रिलेशंस द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि देश पीडीएस के तहत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए गए अनाज का 28 फीसदी इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी सालाना करीब दो करोड़ टन अनाज का लीकेज होता है। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 69 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2.05 लाख करोड़ रुपये का है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से लीकेज में कमी आई है। वर्ष 2011-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46 फीसदी लीकेज है। यद्यपि इस समय इस लीकेज में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी काफी अधिक है। ऐसे में जरूरी है कि पीडीएस के लिए बेहतर निगरानी और संरचनात्मक सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाए।

देश में गरीबों पर केंद्रित लक्षित पीडीएस की शुरुआत जून, 1997 में हुई है। इस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के लिए जाना जाता है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। खासतौर से सितंबर, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पारित होने के साथ ही पीडीएस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। यह अधिनियम देश की 67 फीसदी आबादी को अपने दायरे में लेता है। सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिया जाने लगा है और तब से लगातार अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। सरकार ने वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया है।

देश में कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित रूप से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में पीडीएस की अहम भूमिका है। इससे गरीबी में

कमी आ रही है। कई प्रमुख वैश्विक संगठनों के द्वारा उनकी रिपोर्टों में भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने में 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने और उससे गरीब वर्ग की उत्पादकता बढ़ने के निष्कर्ष भी दिए गए हैं। अमेरिकी के प्रसिद्ध थिंक टैंक द ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां वर्ष 2011-12 में भारत की 12.2 फीसदी आबादी अत्यधिक गरीब थी, वहीं यह वर्ष 2022-23 में घटकर महज दो फीसदी ही रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबों की उत्पादकता वृद्धि, तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को यह कामयाबी मिली है।

लेकिन अभी भी कमजोर वर्ग तक नि:शुल्क गेहूं और चावल के अलावा पोषण युक्त श्रीअन्न यानी मिलेट्स की उपयुक्त आपूर्ति न होने से करोड़ों लोग पोषण सुरक्षा के मद्देनजर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2024 में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। लेकिन भारत के लिए अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में करीब 74 फीसदी लोगों को पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है।

निश्चित रूप से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण, इच्छित लाभार्थियों तक इसकी उपयुक्त पहुंच और पोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर देश की पीडीएस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करना होगा। मौजूदा पीडीएस व्यवस्था को इस तरह सुधारना होगा, जिससे सरकार गरीबों के कल्याण और गरीबी निवारण लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ सके और वास्तविक लाभार्थी इसके लाभों को प्राप्त कर सके। पीडीएस के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में ऐसे परिवर्तन की संभावना तलाशना जरूरी है, जिससे इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और अकुशलता में भी कमी की जा सके।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। चूंकि अभी तक पीडीएस लाभार्थियों में से करीब 64 फीसदी का ही ईकेवाईसी किया गया है, अतएव शेष का ईकेवाईसी तेजी से बढ़ाकर पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

चुनावी हेरफेर का सवाल

उद्देश्य विपक्ष को आगाह करना भर है कि चुनावी हेरफेर का सवाल वे केवल पराजय के दिन उठाएंगे और फिर सब भूल कर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे, तो इस गंभीर मुद्दे पर जनता के बीच कोई नैरेटिव वे खड़ा नहीं कर पाएंगे। महा विकास अघाड़ी की हार के बाद शिव सेना (उद्धव) नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र का मन' जानती है। स्वाभाविक रूप से ऐसा नतीजा नहीं आ सकता था। यानी सत्ता पक्ष ने हेरफेर से चुनाव जीता।

इसी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के एक पराजित उम्मीदवार ने कहा कि 19 से 17 दौर की गिनती तक वे आगे थे। मगर उसके बाद 99 फीसदी चार्ज्ड' ईवीएम निकले, जिनमें अंतर इतना था कि अंतत: वे हार गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने निर्वाचन आयोग पर नियोजित ढंग से चुनावों में समान धरातल खत्म करने का आरोप लगाया। हरियाणा की तरह ही उन्होंने महाराष्ट्र के परिणाम की साख पर गंभीर सवाल उठाए।

साल भर पहले मध्य प्रदेश में हार के बाद वहां के कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगाए थे। यानी अब यह आम रुझान बन गया है। जहां भी विपक्षी दलों की हार होती है, वे उसे सहज स्वीकार नहीं करते। हालांकि इसका कोई ठोस उत्तर उन्होंने पेश नहीं किया है कि सब कुछ मैनेज्ड हो चुका है, तो झारखंड और कश्मीर घाटी में कैसे भाजपा गठबंधन हार गया और लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा को उतना तगड़ा झटका लग गया था।

इस प्रश्न को उठाने का मकसद यहां विपक्षी दलों के संदेह और सवालों को संदिग्ध बनाना या उन्हें निराधार बताना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ विपक्ष को आगाह करना है कि वे ऐसे सवाल केवल चुनावी पराजय के दिन उठाएंगे और दो चार दिन में सब भूल कर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे, तो वे इस गंभीर मुद्दे पर आम जन के बीच कोई नैरेटिव तैयार नहीं कर पाएंगे।

उनकी बातों में तनिक भी दम हो, तो फिर इस वक्त इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा देश के सामने कोई और नहीं है। इसका अर्थ होगा कि देश में लोकतंत्र को सत्ता की मुट्ठी में समेट लिया गया है। मगर आज तक इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर कोई साझा राय या जन अभियान का साझा कार्यक्रम नहीं बनाया। क्यों? इस क्यों' को विपक्ष अब सिर्फ अपनी साख की कीमत पर ही नजरअंदाज कर सकता है।

(ये लेखक के विचार हैं)

श्रीकंचनपथ

भिलाई–दुर्ग

खास खबर

निगम प्रशासन ने 06 कर्मचारियों को स-सम्मान बिदाई दी

भिलाई। नगर निगम भिलाई के सभागार में सोमवार को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 06 कर्मचारियों को स–सम्मान बिदाई दी गई। निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को शॉल और श्रीफल भेंट करते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना किए। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन क्रमांक–1 से यतराम चन्द्रकार पम्प सहायक, संपत्तिकर विभाग से नरहर लाल यादव चैकीदार, जोन क्रमांक–2 से उषा जोशी भृत्य, जोन क्रमांक–2 से बुधरू सफाई कामगार, जोन क्रमांक–4 से ताम्रध्वज बारले सफाई कामगार, जोन क्रमांक–5 से अर्जुनलाल सफाई कामगार को निगम प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सेवानिवृत्त कर्मचारियो ने अपनी कार्य अवधि को याद कर बताया कि कैसी भी परिस्थिति हो हमने निगम के हित को ध्यान में रखकर कार्य किये। नागरिको से जुड़े जो भी कार्य एवं योजना हो उसका बेहतर तरीके से निर्वहन किये। अंत में आयुक्त ने सभी अधिकारी कर्मचारियो से कहा कि जो भी बकाया राशि होगी उसका भुगतान शीघ्र किया जाएगा हम सबको मिलकर के निगम के हित में काम करना है राजस्व की आय बढ़ाना हमारा पहली प्राथमिकता है। निगम के पास जब पैसा रहेगा तभी हम विकास कर सकते हैं, कर्मचारियों का राशि का भुगतान कर सकते हैं, सब काम पैसे पर निर्भर है। इसलिए हम सब का लक्ष्य राजस्व बढ़ता ही होगा। हम सबको मिलकर काम करना है, किसी प्रकार की समस्या होने पर मुझे अवगत करावे, जिससे उसका हल निकालकर उसका शीध्र निराकरण किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास शोभित के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं

दुर्ग। दो एकड़ जमीन में खेती–किसानी व मनरेगा में छोटी–मोटी मजदूरी कर, एक छोटे से कच्चे मकान में गुजर बसर करने वाला मजदूर शोभित राम की यह कहानी है। दुर्ग जिले के अछोटी ग्राम के 45 वर्षीय श्री शोभित राम खेती–मजदूरी से प्राप्त आय को अपने परिवार का भरण–पोषण करने एवं तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शोभित राम ने बताया कि पक्का मकान बनाने का हर व्यक्ति का सपना होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए तो पक्का मकान बनाना एक सपने के समान होता है। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और पक्का मकान बनाने का सपना, सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आया। जब शोभित को इस योजना के तहत पक्के मकान की स्वीकृति मिली, तो यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2019–20 में आवास स्वीकृति हुआ। आवास स्वीकृति उपरान्त प्रथम किश्त 35 हजार, द्वितीय किश्त 45 हजार एवं तृतीय किश्त 30 हजार और चौथी किश्त 10 हजार रूपए प्राप्त हुए। पक्के मकान में दो कमरा और एक किचन कुछ ही महीनों के भीतर तैयार हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण किया गया है।

सार्थी पोर्टल में लंबित आवेदनों के निराकरण पर ध्यान देवें अधिकारी - कलेक्टर चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर समय–सीमा की लंबित प्रकरणों के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन के लंबित आवेदनों के विभागीय निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रकरण लंबे अवधि तक लंबित न रखकर समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिये।

- नगरीय निकाय/पंचायत चुनाव हेतु आवश्यक तैयारियां करें प्रारंभ
- शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने समिति स्तर पर कृषक पंजीयन जरूरी
- पंचायत गबन राशि वसूली पर ध्यान देवें अधिकारी

कलेक्टर ने सार्थी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के संबंध में अवगत कराया कि सार्थी पोर्टल में आम लोगों की आवेदन के अलावा जनसमस्या निवारण शिविर के लंबित प्रकरण भी शामिल किये गये है। अधिकारी प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान देवें। कलेक्टर चौधरी ने जिले में नगरीय निकायों एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने समस्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों को विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की डाटा एन्ट्री एलएमएस की पोर्टल में कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वाहनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभागों में उपलब्ध वाहनों की जानकारी, यदि विभाग में वाहन नहीं है, ऐसी स्थिति में किराये से उपयोग में लायी जा रही वाहनों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। इसी प्रकार विभाग में वाहन नहीं है, लेकिन ड्राइवर पदस्थ है, तो इसकी भी पृथक जानकारी दी जाए।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को क्षेत्र से संबंधित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण/अवलोकन कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। मतदान केन्द्रवार मतदाता संख्या का भी अवलोकन कर लिया जाए। मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार कर किया जाए। जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर मतदाता संख्या आदि के संबंध में अवगत कराएं।

निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी प्रकार निर्वाचन प्रशिक्षण का शेड्युल भी तैयार कर लिया जाए। उन्होंने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को मतगणना स्थल चयन कर आवश्यक व्यवस्थाएं और चुनाव संबंधित लंबित शिकायतें/अपील प्रकरण को समय पर निराकरण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक निधि से ऐसे कार्य जो स्वीकृत है और एक वर्ष से अधिक हो गये कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी विभाग, ऐसे कार्यों की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य नहीं करने वाले कान्ट्रेक्टर को ब्लैक लिस्टेट किया जाए।

कलेक्टर ने अवगत कराया कि कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन व अन्य संबंधित विभाग की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने समिति स्तर पर कृषक पंजीयन जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिक से अधिक कृषकों का पंजीयन कर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपदवार पंचायत गबन राशि की समीक्षा कर अधिकारियों को वसूली हेतु आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के केनाल को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। संबंधित एसडीएम एवं निकाय के अधिकारी अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सर्व विभाग प्रमुख अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों में तीन माह से ऊपर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की सूची कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराने निर्देशित किया हैं। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह व मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं नगर निगमों के सभी आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

हुड़को क्षेत्र में उद्यान, तालाब, स्टेडियम एवं सफाई व्यवस्था का आयुक्त ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय प्रतिदिन सुबह निगम क्षेत्र में हो रहे कार्यो का औचक निरीक्षण कर रहे है। प्रतिदिन अलग–अलग जोन क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर रहे है और वहां पर चल रहे सफाई व्यवस्था को देख रहे है एवं जानकारी प्राप्त कर रहे है। साथ ही क्षेत्र के उद्यानों, तालाबों, स्टेडियम, सड़को पर लगे लाईट व्यवस्था का मॉनिटरिंग भी कर रहे है। जो भी आवश्यक निर्देश है, अधिकारियो को शीध्र दे रहे है।

निगम आयुक्त आज सुबह हुड़को श्रीराम चैंक के आस–पास के उद्यानों को देखने पहुंचे। उन्होने अधिकारी को निर्देश दिए कि उद्यानों में लगाये गये पौधो में पानी की सिंचाई किया जाए, बंद पड़े नल को चालू किया जाए, बिछाए गये पाईप लाईन का संधारण कराए। उसके बाद हुड़को स्थित क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर वहां की सफाई कराने एवं टूटे हुए गेट का संधारण कराने को कहा, जिससे स्टेडियम में जानवर एवं असामाजिक तत्व अंदर न आए। वहां से होकर हुड़को तालाब का निरीक्षण किए तालाब में पूजा सामग्री विसर्जन हेतु कुण्ड बनाने के निर्देश दिए, जिससे आस–पास के नागरिक पूजा सामग्री को उसी में डाले। जिससे तालाब साफ-सुथरा रहे एवं जो स्ट्रीट लाईट बंद पड़े है उसका शीध्र संधारण करने के निर्देश दिए। अंत में शहीद कौशल स्मारक का निरीक्षण किये जहां स्मारक में लगाए गये टाइल्स टूट गये है उसे बदलने के साथ वहां पर लगे पौधो में पानी की सिंचाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, उपअभियंता दीपक देवांगन, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू आदि उपस्थित रहे।

सेल ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। देश की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने आज 3 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करके 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस' मनाया। कंपनी ने इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत आयोजित किया। सेल ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के सहयोग से आयोजित इस पहल के तहत लाभार्थियों की गतिशीलता और संचार को बढ़ाने के लिए ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, स्मार्ट केन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्टफोन और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण वितरित किए।

सेल ने दिव्यांगजनों को उपकरण देने का यह काम लगातार तीसरे साल किया है। इस साल इस कार्यक्रम के साथ चरणबद्ध वितरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे आगे सेल के संयंत्रों और इकाइयों में भी आयोजित किया जाएगा। सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सामाजिक समावेशिता तथा दिव्यांग लोगों के मदद के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने कहा, 'सेल में हम दिव्यांगजनों की अदम्य भावना को सलाम करते हैं। वे अद्वितीय शक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं।

सामुदायिक भवन निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू-महापौर सिन्हा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रिसाली। रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा ने बंद पड़े सामुदायिक भवन निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया है। महापौर और सभापति केशव बंछोर समेत महापौर परिषद के सदस्य पुरैना पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्यो की समीक्षा की।

महापौर सबसे पहले पुरैना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने बन रहे सामुदायिक भवन पहुंचे। शासन स्तर पर 20 लाख स्वीकृत किया गया है। कुछ माह से निर्माण कार्य बंद होने की शिकायत मिलने पर महापौर शशि अपने परिषद के सदस्यों के साथ पुरैना पहुंची थी। स्थानीय पार्षद और नागरिकों से चर्चा करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि कार्य बंद होने का सही कारणों का पता लगाकर वे निर्माण कार्य शुरू कराने सार्थक पहल करेंगी। जहीर अब्बास, सनीर साहू, अनिल देशमुख, चन्द्रप्रकाश सिंह, परमेश्वर कुमार, ममता यादव, डॉ. सीमा साहू, पार्षद रंजीता बेनुआ, पार्वती महानंद आदि उपस्थित थे।

पहले पहुंची अस्पताल

निर्माण कार्य का निरीक्षण करने से पहले महापौर और उनकी टीम अस्पताल पहुंची। प्रभारी डॉक्टर से चर्चा की। वही महापौर ने अस्पताल पहुंचे मरीजों से बातचीत की। बाद में उत्कल नगर में बने भवन को भी देखा। सभापति केशव बंछोर ने छूटे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

पार्षद करे टैक्स जमा करने प्रेरित

महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर ने पुरैना भ्रमण के दौरान स्थानीय पार्षदों से कहा कि निगम का कोष बढ़ाने में प्रयत्न करे। उन्होंने नागरिकों को जल कर और संपत्तीकर, यूजर चार्ज जमा करने आम नागरिकों को प्रेरित करने कहा

शहर की साफ-सफाई में कोताही बरतने वालों पर होगी कार्यवाही : कमिश्नर

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अल सुबह कमिश्नर सुमित अग्रवाल अपने निरन्तर मॉर्निंग विजिट पर वार्ड क्रमांक 54 टीचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने वार्ड क्रमांक 53 माता तालाब पहुँचकर सुपर वाइजर व सफाई कर्मियों को नियमित रूप से तालाब व परिसर के आस पास सफ ाई करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर वार्ड क्रमांक 50 बोरसी क्षेत्र स्थित दोनों शौचालय का अवलोकन कर शौचालय में बेहतर सफाई करने की बात कही।उन्होंने (एसएलआरएम) सेंटर का निरीक्षण कर नियमित रूप से वार्डो की निगरानी करनी चाहिए और स्वच्छता के उपाय करने चाहिए। शहर व दुकान के बाहर सड़क पर गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाही के निर्देश दिए,कचरा संग्रहण वाहनों से वार्डो की निगरानी करे।स्वच्छता दीदी व सफाई मित्र को हर घर से नियमित रूप से कचरा इकठ्ठा करने के लिए कर्तव्य निभाना है। कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने मौजूद अधिकारी को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कचरा हटा रहे हैं, अगर वार्ड क्षेत्र के निवासी को नालियों व सड़क में कचरा फेंकने से मना करें नही माने तो जुर्माना की कार्वाही करें।कमिश्नर ने की अपील नाली ओर खुले स्थानों पर कचरा ना फेके,शहर को स्वच्छ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।सूखा – गीला कचरा अलग अलग एवं नाली ओर खुले स्थानों पर कचरा फेकना देने पड़ सकता जुर्माना। उन्होंने कहा कि नगर निगम स्वच्छता के मामले में जो मुकाम हासिल करना है उसे बरकरार रखते हुए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें।

शहर की साफ-सफाई में किसी के द्वारा भी कोताही बरतने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि शहर के चौक–चौराहों पर कहीं–कहीं कचरे के ढेर दिखाई देते हैं जो शहर की स्वच्छता के प्रतिकूल है निगम के सफाई अमला नियमित सभी वार्डों का निरीक्षण कर सफाई का जायजा लें।

विधायक गजेन्द्र यादव के सफलतम एक वर्ष, कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव

दुर्ग। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार को एक वर्ष होने पर दुर्ग शहर विधानसभा के कार्यकर्त्ताओ ने उत्सव मनाया। विधायक गजेन्द्र यादव के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर केक काटे तथा मिठाई बांटकर खुशियाँ साझा किये। आज सुबह से कार्यकर्त्ता विधायक गजेन्द्र के निज निवास पहुँचे और सेवा के बेमिसाल एक साल का नारा लगाते हुए फूल माला और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनन्दन किये। दुर्ग निगम के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य के राशि स्वीकृत कराने पर नागरिकों ने उनकी मांग पूर्ण कराने पर आभार जताये। उन्होंने कहा हमने जिस विश्वास से हमने गजेन्द्र यादव को चुना वे उस पर खरा उतरे है।

खास खबर...

श्री ठाकुर राम जानकी जी विवाह महोत्सव शुरु, चढ़ाया गया तेल हल्दी

रायपुर। पुरानीबस्ती स्थित श्री जैतूसाव मठ में श्री ठाकुर राम जानकी जी का विवाहोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज हरिद्रालेपन (तेल हल्दी) चढ़ाया गया। महिला मंडली द्वारा छत्तीसगढ़ी पारम्परिक बिहाव गीत गाया गया। मिष्ठान व पकवान का भोग लगाया गया। इस मौके पर मठ के भक्तजन शारदा शुक्ला, शैल अग्रवाल, शालिनी, संतोषी अग्रवाल, सावित्री यदु, स्वाति, प्रमिला, उषा झा, योगिता यदु सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

सिक्ख प्रीमियर लगेज 6 दिसंबर से, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

रायपुर। शहीद भाई तारु सिंह फाउंडेशन रायपुर द्वारा हर साल आयोजित किये जाने वाले नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता इस साल 6 दिसंबर से शुरु हो रही है। सिक्ख प्रीमियर लगेज(एसपीएल)के आयोजन का यह सोलहवां वर्ष हैं। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। संस्था के प्रमुख त्रिलोचन सिंह काले ने बताया कि हर साल ये कोशिश होती है प्राय: सभी प्रमुख शहरों से आने वाली टीमें प्रतियोगिता में शामिल रहे। कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैंजिसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, नांदेड़, नागपुर, हैदराबाद, छत्तीसगढ की टीमें शामिल रहेंगी। बता दें यह क्रिकेट प्रतियोगिता विगत 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। डब्ल्यूआरएस क्रिकेट ग्राउंड में ही मैच खेला जायेगा। फाइनल मैच 16 दिसंबर को होगा। नियमावली हर साल होने वाले आयोजन की तरह ही है। बाबूलाल ज्वेलर्स, जसमीत चावला, बलविंदर सिंह छाबड़ा का सहयोग हर साल मिलते रहा है। मुख्यत: इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में समाज की जो युवा प्रतिभाएं हैं उसे एक मंच प्रदान करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी रहे। इस प्रतियोगिता में खेलने वाले कई खिलाड़ी अपने प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी खेलते आ रहे हैं।

कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध, छुट्टी के दिन भी बुलाये जा सकते हैं कर्मचारी, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसम्बर से शुरू हो रहा है। जिसके चलते विधानसभा सचिवालय से सवाल भी आने लगे हैं। समय-सीमा में सवालों का जवाब बनाना और भेजना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। जिसके मद्देनजर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने समय-सीमा में सवालों का जवाब भिजवाने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर भी नहीं जाएंगे। आकस्मिक हालात में आहूत किये जाने पर कार्यालयीन समय के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय में उपस्थित होंगे। समय-सीमा में विधानसभा के सवालों का जवाब भेजने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर आरए अधारी को नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अधिकारी- कर्मचारी एकता संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महापौर, सभापति, नेताप्रतिपक्ष व आयुक्त मिश्रा को सौंपा ज्ञापन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगो को लेकर महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष मीनल चैबे, आयुक्त अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौपा। जिसमें सभी ने संघ की मांगो को लेकर विचार करने आष्वस्त किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष प्रमोद जाधव, उपाध्यक्ष स्वाती साहू, मोहित कुमार, श्याम सोनी, महामंत्री आषुतोष सिंह, राधेष्याम एक्का सहित अन्य पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित थे।

नगर पालिक निगम, रायपुर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे निम्न है 2004 के बाद नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया जाये। बीमार अधिकारी एवं कर्मचारियों के त्वरित इलाज हेतु कैशलेस कार्ड की सुविधा प्रदान करते हुए 15 लाख के स्थान पर 25 लाख की सुविधा प्रदान की जायें। पात्र अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय-पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे साथ ही समय पर अपने उच्चतर शिक्षा ग्रहण एवं अन्य परीक्षा इत्यादि में शामिल होने वाले कर्मचारियों के आवेदन पर शीघ्र विचार कर नियमानुसार अनुमति व अनापत्ति प्रदान किया जावें। मृत अधिकारी एवं कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को शीघ्र ही अनुकम्पा नियुक्ति दिया जावे। नगर निगम रायपुर में ठेका पद्धत्ति समाप्त किया जाकर प्लेसमेंट कर्मचारियों को सीधे निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावें। ठेका में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जायें।

आयुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में ली बैठक

नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा निगम सभाकक्ष में साफ - सफाई स्वच्छता संबंधी बैठक ली। बैठक में अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही, कार्यपालन अभियंता रधुमणी प्रधान, जोन कमिश्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, रामकी कंपनी के प्रतिनिधियों, रोड स्वीपिंग मशीन के प्रतिनिधिगण, सफाई ठेकेदार उपस्थित रहे। आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया कि शहर में घरों से निकलने वाले कचरे का डोर टू डोर कलेक्षन कर शत प्रतिषत सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही सफाई कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देष जोन कमिश्नरों व जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये।

आयुक्त ने निर्देशित किया कि शहर में कही भी कचरा ना दिखे ऐसे जोन स्तर पर सफाई व्यवस्था करने कहा ताकि शहर के लोगो को अच्छी सफाई व्यवस्था का लाभ मिल सके। आम नागरिकों द्वारा किसी प्रकार की सफाई संबंधी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सड़कों की अच्छी तरह सफाई करने के निर्देश दिये। आम नागरिको से प्राप्त सफाई संबंधी जनशिकायतो का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये।

साइंस कॉलेज का चौपाटी बंद, आमानाका ओवरब्रिज के नीचे किया जा रहा शिफ्ट

यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया, निगम व ठेका एजेंसी मिलकर निकाले समाधान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। साइंस कॉलेज मैदान के पास स्थित चौपाटी को बंद कर अब इसे आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी ने चौपाटी का ठेका लेने वाली एजेंसी को निर्देश दिया है कि दुकानों को नई जगह पर स्थानांतरित किया जाए।

सोमवार को कुछ दुकानों को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि बाकी दुकानों की शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें दोनों पक्षों - नगर निगम और ठेका एजेंसी को मिलकर समाधान निकालने को कहा गया था।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रैफिक, बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के माहौल को ध्यान में रखते हुए साइंस कॉलेज चौपाटी को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। आमानाका वेंडिंग जोन को नई जगह के रूप में चुना गया है। यहां पर चौपाटी जैसी ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

वेंडरों का कहना है कि उन्हें शिफ्टिंग के लिए बहुत कम समय दिया गया है। नई जगह पर बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का

अभाव है। अधिकारियों ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया था, और कुछ दुकानों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। वेंडरों को चेतावनी दी गई है कि वे समय पर न शिफ्ट होने पर निगम जबरन स्थानांतरित कर देगा।

चौपाटी का निर्माण कांग्रेस सरकार के दौरान रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय की पहल पर हुआ था। उस समय भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसका विरोध किया था और इसे लेकर आंदोलन भी किया था। चौपाटी को हटाने का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां फरवरी में ठेका एजेंसी का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। शिफ्टिंग के बाद आमानाका वेंडिंग जोन में चौपाटी जैसी सुविधाएं देने की योजना बनाई गई है। हालांकि, वेंडरों की मांग है कि पहले सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। नगर निगम ने इस पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

पुण्य और पाप हमारे अच्छे, बुरे कर्मो के कारण बनते है : पुनीत सागर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य आगम सागर महामुनि, पुनीत सागर महामुनिराज व ऐलक धैर्य सागर महामुनिराज का मंगल प्रवेश राजधानी के आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर (लघु तीर्थ) मालवीय रोड में 2 दिसंबर को हुआ। महाराज के मंगल प्रवेश और पावन सानिध्य से संपूर्ण समाज में उल्लास छा गया।

पुनीत सागर महामुनिराज ने अपने मुखाग्रबिंदु से प्रवचन में बताया कि पाप और पुण्य हमारे अच्छे और बुरे कर्मो कार्यों के कारण बनते है। जैसे हम अपने अपने दैनिक जीवन में अच्छे कार्य करते है देव, शास्त्र, गुरु के बताए मार्ग पर चलते है। तो हमे इसके अच्छे परिणाम इस जीवन के आलावा अगले पर्याय में भी मिलते है। और अगर हम सदा बुरे, पाप के कार्यों में लगे रहते है तो इसके परिणाम हमेशा बुरे मिलेंगे और जब भी कोई जीवन हमे मिलेगा तो चाहे कितने अच्छे कार्य कर लो पहले पूर्व मै किए बुरे कार्यों का परिणाम भोगना पड़ेगा। अच्छे पुण्य कार्यों से आत्मा पवित्र होती है। और पाप कार्यों से दुर्गति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति देव शास्त्र गुरु पर विश्वास रख कर यह वहा नहीं भटकता उसे हमेशा सद्गति प्राप्त होती है। कभी नरक गती नहीं मिलती,अच्छा कुल प्राप्त होता है, नपुंसकता नहीं होती।उच्च कुल की प्राप्ती होती है।घर में हमेशा हर्ष का वातावरण होता है। ठीक इसके विपरीत अगर बुरे कार्यों को करते है तो पिछले बुरे कार्यों को पहले भुगतना पड़ता है नीच कुल में जन्म मिलता है दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता है घर में सब बीमार और जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फदवाईयो का सेवन करना पड़ता है। इसलिए समय का लाभ लेकर हमेशा लेकर अच्छे कार्य करना चाहिए।

आगम सागर महाराज ने अपने प्रवचन मै बताया कि आचार्यश्री अपने जीवन को लोहे कि तरह जिया। जीवन भर किसी भी सहारे में नहीं रहे। अपने अन्तिम समय में भी वो अपने सभी नियमों का पालन करते रहे। उनकी कृपा से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्र गिरी का विशाल तीर्थ बन रहा है। यहां तीर्थ थे नहीं। आज भारत के साथ साथ विदेशों ने भी छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान बन गई है। आचार्य श्री इस धरती के ऐसे संत थे जो ख्याति पूजा लाभ से हमेशा दूर रहे। उन्होंने कभी किसी भी धर्म उनके गुरु किसी व्यक्ति को कभी कुछ नहीं कहा। वो स्वयं कम बोलते थे हमेशा उनके काम बोलता था। आज जिस स्थान पर उनकी समाधि है वह छत्तीसगढ़ मै रायपुर के निकट है ये रायपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है।उनके प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य पर 1008 श्री सिद्ध चक्र महा मंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है जिस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में धर्म प्रेमी बन्धुओ को भाग लेना चाहिए। साथ ही आचार्य श्री ने राजधानी के आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर को लघु तीर्थ बनाने का को मंगल आशीर्वाद दिया है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा।

एनआईटी रायपुर ने मनाया अपना 20वां स्थापना दिवस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर ने सोमवार को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के रूप में स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान को 1 दिसंबर 2005 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। संस्थान के 20वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बीएल थे। छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल के सीजीएम विजय कुमार छबलानी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के निदेशक डॉ. के. के. शुक्ला इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। समारोह की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एनवी रमना राव ने की। कार्यक्रम में सभी डीन, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की

शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई और इसके बाद गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया।

एप्लाइड जिओलोजी विभाग के प्रोफेसर प्रभात दीवान ने एनआईटी रायपुर की पारदर्शिता, सुशासन और नवाचार प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अटल रैंकिंग, इनोवेशन सेंटर, सीड ग्रांट, प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं और एनईपी 2020 व विजन 2030 के कार्यान्वयन को रेखांकित किया। उन्होंने वर्तमान में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हुए संस्थान के भविष्य को आकार देने का सभी से आह्वान किया। इसके बाद एनआईटी रायपुर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जिसमें संस्थान की उपलब्धियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया।

डॉ. रमना राव ने अपने भाषण में संस्थान की यात्रा पर विचार करते हुए बौद्धिक विकास, प्रतिभा संवर्धन और रचनात्मकता पर जोर दिया। उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं, अनुसंधान में उत्कृष्टता और संकाय, छात्रों व कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की सराहना की। शैक्षणिक, शोध और उद्योग में संस्थान की प्रमुख भूमिका की पहचान करते हुए, उन्होंने सभी को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया, साथ ही पूर्व छात्रों के योगदान की सराहना की । के.के. शुक्ला ने संस्थान की उपलब्धियों के लिए सभी को बधाई दी ।

उन्होंने संस्थान के पूर्व छात्रों के समर्पण और प्रतिबद्धता को सराहा और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का उद्धरण दिया जो मानव प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने एनआईटी रायपुर के नेतृत्व और छात्रों की सराहना की, उन्होंने संस्थान के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। विजय कुमार छबलानी जी ने अपने छात्र जीवन से सीखे गए महत्वपूर्ण मूल्यों को याद किया । उन्होंने अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और आजीवन शिक्षा और कठिन मेहनत पर जोर दिया।

सेल्फ स्टडी करने और धैर्य रखने वाले साधारण व्यक्ति को निश्चित मिलती है सफलता: आनंद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जाने-माने शिक्षाविद, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सुपर 30 के आनंद कुमार राजधानी रायपुर के नवगुरूकुल में छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे। आनंद कुमार ने छात्र-छात्राओं को सफलता हासिल करने के मूलमंत्र बताए। आनंद कुमार ने कहा कि सपना देखना चाहिए और हर परिस्थितियों में समझौता भी नहीं करना चाहिए। जिद भी व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, तब उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि रास्ते खुद से खोजें। पढ़ाई में किसी भी चीज को रटने का काम नहीं करना चाहिए। क्यों के सवाल को ढूंढे। इससे आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

आनंद कुमार ने अपने अनुभव शेयर करते हुए युवाओं से कहा कि मनुष्य में आत्मविश्वास कमी नहीं होनी चाहिए। हर दिन बेहतर करने की सोच होनी चाहिए। संघर्ष करना भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर तमाम टूल्स हैं, जिसका उपयोग भी सकारात्मक चीजों के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बाधा को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है और मृदुभाषी भी बनना आवश्यक है। आनंद कुमार ने नवगुरूकुल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने पर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हमेशा कड़ी मेहनत कीजिए और नई उंचाईयों को छूने की ताकत रखिए। इस दौरान आनंद कुमार ने नवगुरूकुल के छात्रा-छात्राओं के साथ सेल्फी भी खिंचाई।

यू आर द लास्ट वन, नताशा स्तांकोविक ने कही अपने दिल की बात, लोगों ने लगाई अटकलें

एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्तांकोविक और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने शादी के चार साल बाद इस साल जुलाई में अपने तलाक की घोषणा की थी। एक्ट्रेस अपने दोस्त अलेक्जेंडर एलेक्स को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और अपनी लाइफ के अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस ने तरह-तरह की अटकलें लगाना शुरु कर दिया है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा कि यू आर द लास्ट वन, सो बी द बेस्ट वन। इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट दिल इमोजी भी शेयर किया है।

एक्ट्रेस ने हाल ही में हार्दिक से अपने अलग होने का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर जैसे ही दोनों के अलग होने का पोस्ट सामने आया, तो इंटरनेट पर हलचल बढ़ गई और किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि दोनों अलग हो रहे हैं। हार्दिक से अलग होने के बाद नताशा को अक्सर उनके बेस्ट फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ देखा जाता है। वहीं एक्ट्रेस ने एक बार सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी शेयर की थी कि एक्ट्रेस और एलेक्स दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यूजर्स ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है और यूजर्स अलग- अलग कयास लगा रहे हैं।

दरअसल, एक्ट्रेस ने ये पोस्ट दिसंबर के लिए डाला था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि हे दिसंबरज यू आर द लास्ट वन, सो बी द बेस्ट वन। इसी के साथ उन्होंने एक व्हाइट दिल वाला इमोजी भी लगाया था। वहीं अब लोग इस पोस्ट के बाद अलग-अलग अटकलें लगा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि एक्ट्रेस का इशारा कई और ही है। इन दिनों नताशा अकेली हैं, तो जाहिर है कि उनका एक हल्का-सा इशारा लोगों में चर्चा का विषय बन सकता है।

स्विमिंग करने से पहले ज्यादा खाना खाने से पेट में हो सकता है दर्द

तैराकी से पहले बहुत ज़्यादा खाने से पेट में दर्द होता है इस बात का कोई मेडिकल सबूत नहीं है कि खाने के बाद तैरने से गंभीर ऐंठन या डूबने की संभावना होती है। शरीर पेट और मांसपेशियों दोनों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तैराकी से पहले खाना मनोरंजक तैराकी के लिए सुरक्षित है। सबसे बड़ा खतरा शायद मामूली ऐंठन है।

तैराकी से पहले खाने के कम से कम 30 मिनट बाद तक इंतजार

यह मिथक कि आपको तैराकी से पहले खाने के कम से कम 30 मिनट बाद तक इंतजार करना चाहिए। इस विचार से आता है कि खाने से रक्त पेट और आंतों में चला जाता है। हालांकि, शरीर पाचन में सहायता के लिए अतिरिक्त रक्त की आपूर्ति करता है, लेकिन मांसपेशियों को ठीक से काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं देता है। तैराकी करते समय अपने पेट में हवा जाने से बचने के लिए।

आप कार्बोनेटेड पेय और च्युइंग गम का सेवन सीमित कर सकते हैं। आपको तैराकी से पहले आलू के चिप्स या फ्राइड चिकन जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए।सांस लेने की गलत तकनीक की वजह से तैराक हवा निगल सकता है, जिससे तैरने के बाद डकार, गैस और पेट में दर्दनाक ऐंठन हो सकती है। एरोफेगिया के नाम से जानी जाने वाली यह आदत जठरांत्र संबंधी मार्ग में हवा को फंसा देती है। नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन के डाइजेस्टिव हेल्थ सेंटर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन स्टीवॉफ ने हेल्थ को बताया कभी-कभी पेट में असुविधा और दर्दनाक शौच लैक्टोज फ्रुक्टोज या ग्लूटेन जैसे खाद्य असहिष्णुता के कारण हो सकता है। स्विमिंग से पहले कम से कम 30 मिनट पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से खाना ठीक से पचता नहीं और तैरते समय परेशानी हो सकती है। हालांकि, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, तो खाना खाने के बाद भी तैर सकते हैं। इससे पाचन में सुधार होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं।

स्विमिंग से पहले क्या खाना चाहिए

स्विमिंग से पहले आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि फल, उबली सब्ज़ियां, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, ब्रेड, नट्स, और साबुत अनाज। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, जूस, अखरोट का दूध, या स्मूदी पिएं। प्रोटीन का सेवन करें ताकि शरीर को ऊर्जा और ताकत मिल सके। तैराकी से पहले भारी खाना न खाएं, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, पराठे, या पूरी। तैराकी से पहले तले-भुने, मसालेदार, रेशेदार खाद्य पदार्थ, उच्च चीनी कार्बोनेटेड पेय, और कैफ़ीन-आधारित पेय न खाएं।

वनवास का ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए नाना व उत्कर्ष

निर्देशक अनिल शर्मा पिछले काफी समय से फिल्म वनवास को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो उनकी फिल्म गदर और गदर 2 में थे। फिल्म में नाना पाटेकर भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के पोस्टर से लेकर टीजर और गाने तक दर्शकों को बेहद पसंद आए हैं। अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

ट्रेलर की शुरुआत में उत्कर्ष कहते हैं, माता-पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म होता है मां-बाप को संभालना। फिल्म की कहानी उन लोगों पर है, जो पालकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां-बाप को छोड़ देते हैं। नाना ऐसे ही शख्स के किरदार में हैं, जिन्हें उनके बच्चों ने उन्हें रास्ते पर छोड़ दिया है।ट्रेलर में भावुक कर देने वाले पल हैं।

एक यूजर ने लिखा, मारधाड़ वाली फिल्मों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय वाली फिल्म का ट्रेलर देख मजा आ गया। वाह! एक लिखते हैं, मैं फिल्म का पहले दिन का पहला शो देखूंगा। ऐसी फिल्मों को समर्थन मिलना चाहिए। एक ने लिखा, क्या गजब ट्रेलर है। ऐसा सिनेमा तो अब खो ही गया है। एक लिखते हैं, पिछले कुछ सालों से ऐसी ही फिल्म की तलाश थी, वहीं कुछ को सिमरत कौर और उत्कर्ष की केमिस्ट्री भी पसंद आई है।

निर्देशक अनिल शर्मा कहते हैं, यह फिल्म मेरे बेहद करीब है, क्योंकि ये प्यार, बलिदान और परिवार के असली मतलब को समझाती है। नाना, उत्कर्ष, सिमरत, राजपाल यादव और बाकी कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों से फिल्म में गहरी और असली भावनाएं डाली है। मैं दर्शकों को उनका सफर पर्दे पर दिखाने के लिए काफी उत्साहित हूं।उधर नाना के मुताबिक, वनवास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन भावनाओं का आईना है, जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर दबाकर रखते हैं। ज़ी स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी। पिछली बार अनिल फिल्म गदर 2 लाए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड बनाए और धराशायी किए। फिल्म में उत्कर्ष और सिमरत दिखे थे। वनवास में यह जोड़ी दोबारा दर्शकों का दिल जीतने आ रही है। इस फिल्म में परिवार के सच्चे अर्थ को दिखाया गया है और बताया गया है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और स्वीकार्यता से बनते हैं।

शरवरी वाघ ने स्टाइलिश आउटफिट में कराया हॉट फोटोशूट, बोल्डनेस ने इंटरनेट का बढ़ाया तापमान

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ हमेशा अपने स्टनिंग और हॉट लुक्स से सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटौरती रहती हैं। उनका कातिलाना लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से बवाल मचाने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें फैंस के बीच साझा की हैं। इन फोटोज में उनका सिजलिंग अंदाज देखकर फैंस एक बार फिर से अपने होश खो बैठे हैं।

मुंजिया फेम शरवरी वाघ पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनका कातिलाना अवतार इंटरनेट पर आते ही छा गया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस बेहद ही स्टनिंग और हॉट लुक में फोटोशूट करवाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि शरवरी वाघ जब भी अपनी फोटोज इंस्टा पर पोस्ट करती हैं तो वो चंद ही मिनटों में वायरल होने लगती हैं।

हालांकि इन फोटोज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शरवरी वाघ ने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान ब्राउन कलर की कोट लुक मं ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद ही शानदार नजर आ रही हैं। खुले बाल, कानों में इयररिंग्स और ग्लैम मेकअप कर के एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है। साथ ही कैमरे के सामने स्टनिंग पोज देती हुई एक्ट्रेस हॉट फोटोज क्लिक करवा रही हैं।

इंडियन हो या फिर वेस्टर्न लुक एक्ट्रेस शरवरी वाघ अपने हर एक लुक में बेहद ही शानदार नजर आती हैं। बताते चलें कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया लवर हैं और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। साथ ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए अपडेट्स भी फैंस के बीच शेयर करती रहती हैं।

द डर्टी पिक्चर वाली सिल्क स्मिता की बायोपिक का एलान

चंद्रिका रवि करेगी क्वीन ऑफ द साउथ का रोल, फर्स्ट लुक भी आया सामने

विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म द डर्टी पिक्चर तो आपने देखी ही होगी। द डर्टी पिक्चर साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर आधारित है। द डर्टी पिक्चर को मिलन लूथरिया ने डायरेक्ट किया था, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी और इस फिल्म से विद्या बालन का करियर टॉप पर पहुंच गया था। अब दिवंगत साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी बायोपिक सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ का एलान हुआ है और साथ ही एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक भी सामने आया है।

बता दें, एसटीआरआई सिनेमास ने सिल्क स्मिता की बायोपिक का एलान किया है। इसमें भारतीय मूल की आस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस चंद्रिका रवि एक्ट्रेस सिल्क स्मिता का रोल करने जा रही हैं। बायोपिक सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ के टीजर में चंद्रिका रवि का बतौर सिल्क स्मिता फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसमें वह बेहद सुंदर दिख रही हैं। बता दें, बायोपिक सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ का निर्देशन जयराम शंकरण कर रहे हैं और एसबी विजय अमृतराज बायोपिक के निर्माता हैं।

वहीं, मेकर्स ने सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ अनाउंसमेंट टीजर शेयर किया है, जिसमें सिल्क स्मिता का चंद्रिका रवि के रूप में फर्स्ट लुक दिख रहा है। टीजर की शुरुआत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के केबिन से शुरू होता है, जिसमें वह कुछ अखबार और मैगजीन में देखती हैं कि हर तरफ सिल्क स्मिता छाई हुई हैं। इतना देखने के बाद श्रीमति इंदिरा गांधी पूछती हैं यह सिल्क कौन हैं इसके बाद सिल्क स्मिता के रोल में चंद्रिका रवि कार से अपने सिजलिंग लुक में निलकती हैं और लोगों की नजरें उनपर टिक जाती हैं। वहीं, सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ बायोपिक के लिए दर्शकों के लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बायोपिक सिल्क स्मिता- क्वीन ऑफ द साउथ अगले साल 2025 के शुरू में फ्लोर पर आएगी।

सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को एलुरू (आंध्र प्रदेश) में हुआ था और 23 सितंबर 1966 को महज 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। सिल्क ने अपने 17 साल के फिल्मी करियर में पांच भाषाओं में 450 फिल्में की थी। सिल्क का असली नाम विजयालक्ष्मी विदलपति था। वहीं, इनका स्टेज नेम सिल्क स्मिता था।

प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज सही है या नहीं जानें क्या है पूरा सच

पांच में से एक गर्भवती महिला को कम फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है। भले ही एक्सरसाइज को ज़्यादातर गर्भावस्थाओं के दौरान सुरक्षित और हेल्दी माना जाता है। हालांकि कुछ डॉक्टर कुछ गर्भवती महिलाओं की कंडीशन देखकर फुल बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। हालांकि, जिन महिलाओं की हेल्दी प्रेग्नेंसी हैं उन्हें एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं।

गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने के बारे में कई मिथक हैं। लेकिन व्यायाम आम तौर पर सुरक्षित है और ज़्यादातर महिलाओं के लिए अच्छा होता है। आपको गर्भावस्था के दौरान व्यायाम शुरू नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था व्यायाम शुरू करने का एक बढ़िया समय है। भले ही आपने पहले कभी व्यायाम न किया हो। व्यायाम बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। मध्यम व्यायाम आम तौर पर सुरक्षित है और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है।

आप उच्च-प्रभाव वाली गतिविधियां नहीं कर सकते

यदि आप गर्भावस्था से पहले सक्रिय थीं, तो आप उच्च-प्रभाव वाली गतिविधियां जारी रख सकती हैं, लेकिन आपको अपने शरीर की बात सुननी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना चाहिए। पेट की कसरत नहीं कर सकते। गर्भावस्था के दौरान कोर की ताकत महत्वपूर्ण है, और पेल्विक टिल्ट या प्लैंक वेरिएशन जैसे सुरक्षित कोर व्यायाम मदद कर सकते हैं।

आपकी हृदय गति कभी भी 140 बीपीएम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अधिकांश डॉक्टर अब आपको सलाह देते हैं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रही हैं और यदि आप आराम से बातचीत नहीं कर सकती हैं तो व्यायाम करना बंद कर दें। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने या जारी रखने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। अगर आप गर्भावस्था से पहले बहुत सक्रिय नहीं थीं। तो हल्के व्यायाम से शुरुआत करें, जैसे कि टहलना। यह कहने का मतलब है हल्के एक्सरसाइज।

सैनिकों के कल्याण के लिए मानवीय संवेदना से कार्य करें - राज्यपाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्त्तव्य है। इसमे मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल डेका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ''सशस्त्र सेना झंडा'' दिवस निधि के लिए संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड एवं गृह विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सहायता

भूतपूर्व सैनिकों के हितों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्ण सैनिक उनके लाभान्वित होंगे।

श्री डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।

बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टेड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्त प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षु को देय 5 हजार रूपए प्रति माह के स्थान पर प्रशिक्षु द्वारा संस्थान को देय वास्तविक शुल्क प्रदान किया जायेगा तथा लघु व्यवसाय हेतु देय आर्थिक अनुदान 15 हजार रूपए जो सैम्फेक्स योजनाओं में सम्मिलित नहीं थे उनको वृद्धि कर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक विवेक शर्मा ने बोर्ड की अब तक की गतिविधियों एवं बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, गृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता, वित्त विभाग की सचिव शारदा वर्मा, ब्रिगेडियर प्रशासन, मध्य भारत एरिया, ब्रिगेडियर एस. के. मल्होत्रा, कार्यवाहक सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली कैप्टेन (भा.नौ.) शाश्वत पूर्णानंद, अतिरिक्त महानिदेशक, पुनर्वास परिक्षेत्र मध्य कमान, लखनऊ ब्रिगेडियर विक्रम हिरू, कर्नल सुमीत शर्मा प्रभारी कमान्डर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया (कोसा) ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में अशासकीय सदस्यगण मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.), विंग कमाण्डर ए श्रीनिवास राव (से.नि.), गैर शासकीय सदस्य द्वय कैलाश नाहटा एवं श्री टी आर साहू उपस्थित थे।

गोविन्द के रंग-बिरंगे गुलाबों की प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बिखर रही खुशबू

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि दुनियाभर में गुलाब के फूल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। गुलाब की पंखुडियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह मुहांसों को सूखने में मदद करता है। इसके साथ ही भगवान की पूजा-पाठ से लेकर कई स्किन एलर्जी और देशी इलाज के लिए भी इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है।

यही वजह है कि धमतरी जिले के कुरूद विकासखण्ड के ग्राम राखी के किसान गोविन्द चन्द्राकर ने गुलाब फूलों की बागवानी करने की मन में ठानी। इसके लिए उन्होंने उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन लिया और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना के तहत अपने ढाई एकड़ रकबा में नेचुरल वेंटीलेटेड पॉली हाउस का निर्माण किया। कभी धान, दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसान अब गुलाब के फूलों से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटे हैं।

किसान गोविन्द चन्द्राकर बताते हैं कि वे ड्रीप पद्धति के माध्यम से गुलाब की खेती पिछले तीन सालों से कर रहे हैं, इससे पानी की बचत तो होती ही है। उनके ढाई एकड़ रकबा में 9 लाख गुलाब स्टीक तैयार कर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विक्रय किया, जिससे उन्हें 16 लाख रूपये की आमदनी हुई है। गोविन्द चन्द्राकर खुश होकर बताते हैं कि उन्हें गुलाबों से प्रति एकड़ चार लाख रूपये की शुद्ध आमदनी हो रही है। उनके गुलाब अन्य राज्यों में भी अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं।

कलेक्टर ने क्लिक सेफ कार्यक्रम का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास के दिशा-निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से सक्लिकसेफ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसका शुभारंभ कलेक्टर व्यास द्वारा किया गया।

कार्यक्रम की शुभारंभ के साथ ही एसपी कार्यालय परिसर और पुलिस लाइन के मीटिंग हॉल तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है जिसमें 03 एवं 04 दिसंबर को सभी थानों से उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी प्रकार 05 दिसंबर को होने वाले प्रशिक्षण में जय हो कार्यक्रम से जुड़े एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर श्री व्यास ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सक्लिकसेफ कार्यक्रम के उददेश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर खतरों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। रुक्लिकसेफ अभियान के तहत यह कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने और ऑनलाइन जोखिमों से बचाव के उपाय सिखाने पर केंद्रित है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना है। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी, जैसे पासवर्ड प्रबंधन, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, और साइबर बुलिंग से बचाव के उपाय। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना है।

इस अवसर पर प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री अनिल सोनी, यूनिसेफ से बाल संरक्षण विशेषज्ञ श्री चेतना देसाई, बाल संरक्षण कंसलटेंट गीतांजोलि दास गुप्ता, बाल संरक्षण कंसलटेंट अभिषेक कुमार, दिल्ली के मास्टर ट्रेनर्स हिमानी चौहान, सीनियर ऑफिसर, प्रोग्राम्स, वाईएलएसी, निधि किन्हल, प्रोग्राम्स ऑफिसर, वाईएलएसी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य के दिव्यांगजनों के हितसंरक्षण के लिए अनेक योजनाएं हो रही संचालित : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

समाज कल्याण मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग भुवनेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जांजगीर-चांपा जिले के सेवा समिति संस्थान को तथा नि:शक्तजन कल्याण संघ को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राइसाइकिल तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी के श्रवण बाधित श्रेणी में कोरबा जिले के प्रकाश खाकसे को अस्थि बाधित श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिले के संतोष बंजारे को पुरस्कृत किया गया।

मतदाता सूची प्रकाशन के पूर्व सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराएं: अजय सिंह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग अटल नगर नवा रायपुर कार्यालय के सभा कक्ष में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम/उप निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचन कार्यों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में रायपुर संभाग के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, संभाग के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी अधिकारियों से शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची प्रकाशन के पूर्व सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली को सभी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखे, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने, और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों के निर्वाचन की तैयारी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि आप सभी अपनी तैयारीयों की समीक्षा करते रहें। गत 26 नवम्बर को बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग तथा 29 नवम्बर को दुर्ग संभाग के अधिकारियों की चुनाव तैयारी के संबंध में समीक्षा की जा चुकी है कल 4 दिसंबर को बस्तर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सुरक्षा उपायों और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती, और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय पर सही जानकारी प्रदान करें।

दिव्यांगों को ईश्वर ने दी है अप्रतिम प्रतिभा, सामर्थ्य एवं शक्ति : कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि ईश्वर ने दिव्यांगों को अप्रतिम प्रतिभा, सामर्थ्य एवं शक्ति दी है। जो कि अपने दृढ ईच्छा, शक्ति एवं जिजीविषा के बलबूते पर नि:शक्तता के उपरांत भी एक सामान्य व्यक्ति की भाँति सभी कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित कर रहे हैं।

श्री चन्द्रवाल जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम सिवनी में स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। श्री चन्द्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित दिव्यांगजनों को शॉल, श्रीफल से सम्मानित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश सूर्यवंशी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग अजय कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि आज उन्हें दिव्यांगों के बीच उपस्थित होकर हार्दिक प्रसन्नता एवं आत्मीय संतुष्टी हो रही है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आज दिव्यांगों से मुलाकात करने की उनकी बहुप्रतिक्षित मंशा भी पूरी हो रही है। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों के नि:शक्तता प्रमाण पत्र बनाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सप्ताह में दो दिन दिव्यांगों के बीच पहुँचकर उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु उन्हें शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराने जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों के बीच पहुँचकर उन्हें मिष्ठान भी वितरण किया।

विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग बच्चों को उपकरणों का वितरण

कवर्धा। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विकासखंड बोड़ला में दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुसार उपकरण वितरित किए गए। यह कार्यक्रम कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी और समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयक के निर्देशानुसार 12 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, रोलेटर और होम बेस्ड एजुकेशन के तहत किट और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण प्रदान कर उन्हें शाला में नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया गया कि उपकरण उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन में सहायक सिद्ध हों।

कार्यक्रम में बच्चों और उनके पालकों ने खुशी जाहिर की। कलेक्टर गोपाल वर्मा और सीईओ अजय त्रिपाठी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और समावेशन में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.एल. पंद्रो, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरिकृष्ण नायक, खंड स्त्रोत समन्वयक राजेंद्र कुमार सोनी, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोड़ला अश्वनी सोनी और बीआरपी गायत्री प्रसाद साहू विशेष रूप से उपस्थित थे।

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स
जींस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं किट्स वियर,अंडर गारमेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन
एक बार अवश्य पधारें
गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok
JEWELLERY
Gifts ● Toys ● Cosmetics
Perfumes ● Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

खास खबर

पिकअप और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर-अंबिकापुरमार्ग पर गोटगवां के पास देर रात एक पिकअप वाहन और कार की आमने सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

प्रतापपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोवर्धनपुर से कार क्रमांक सीजी 29 एई 7704 में सवार होकर चार युवक अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे प्रतापपुर-अंबिकापुर मार्ग (खड़गवां रोड) में स्थित गोटगवां के नजदीक टमाटर लोड कर बनारस जा रहे तेज रफ्तार पिक?अप वाहन क्रमांक यूपी 64 एटी 6380 से कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गोवर्धनपुर निवासी 24 वर्षीय प्रियांशु पटेल, दीपक पटेल (23 वर्ष) तथा पुष्पेंद्र पटेल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि कार में सवार 21 वर्षीय युवक विनय निवासी बटई तथा पिकअप चालक 42 वर्षीय फुन्दुरडिहारी निवासी विक्रम सिंह की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज मेडिकल कालेज अंबिकापुर में जारी है।पुलिस मामले की जांच कर रही है।

धारदार चाकू लेकर खड़ा था बदमाश पुलिस ने मौके पर दबोचा

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड पर हैं। अपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने धारदार चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बूढ़ा तालाब गार्डन के पास में एक व्यक्ति खड़ा है। वह अपने पास अवैध रूप से चाकू रखा है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर रवाना होकर मुखबिर के बताए अनुसार जगह पर पहुंची। इस दौरान अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिश की, लेकिन भागने में असफल रहा। आरोपी का तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से एक नग लोहे की धारदार चाकू मिला। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफआर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया।

55 हजार रुपये नकद, ताश के 52 पत्ते सहित 8 जुआरी गिरफ्तार

जगदलपुर। जिले के नगरनार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवड़ा मंदिर काजू प्लांट में जुआ खेलते आठ जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 55 हजार रूपये से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि देवड़ा मंदिर काजू प्लांट के पास एवं ग्राम गरावंड खुर्द के जंगल में जुआ की महफिल सजी हुई है। सूचना पर नगरनार पुलिस रेड की कार्रवाई के लिए निकले थे। जैसे ही जवान मौके पर पहुंचे तो फड़ में मौजूद जुआरी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने मौके से आठ जुआरियों सुजय बिसाई, बिगना पटनायक, छोटु बघेल, मनोज सेठिया, महेश बघेल, बसंत बघेल, रामसर बघेल को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 55460 रूपये नगद, ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया ।

साइबर क्राइम पर किया फोकस, दुर्ग पुलिस ने ली बैंक प्रबंधकों की बैठक, दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। पुलिस कण्ट्रोल रूम सेक्टर-06 भिलाई में एएसपी सुखनंदन राठौर की उपस्थिति में शहर के बैंक प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान साइबर ठगी के बढ़ते अपराध के तरीकों से बैंक अधिकारियों को अवगत कराया गया। इन अपराधों के रोकने, पीड़ितों को अविलम्ब सहयोग पहुंचाने, गोल्ड लोन वाले मामलों की पूर्ण तस्दीक किए जाने, बैंकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक चर्चा की गयी। यह बैठक दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला निर्देश पर आयोजित की गई।

बैठक में एएसपी सुखनंदन राठौर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि साइबर क्राइम के अपराधों में पुलिस के साइबर सेल व्दारा चाही गयी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराने कहा। इस दौरान रकम होल्ड, अनहोल्ड करने संबंधी बैंक की कार्यवाही तत्परता से करने ताकि पीड़ितों को राहत मिल सकें। एटीएम के फूटेज तत्काल उपलब्ध कराया जाए जिससे जांच तेजी से हो। प्रत्येक एटीएम में 24 घण्टे सुरक्षा गार्ड रखा जाए एवं सुरक्षा गार्ड के माध्यम से एटीएम में मुंह में गमझा या नकाब पहनकर एटीएम का उपयोग न करने दिया जाए।

बैंक खाता होल्ड होने की पुलिस को दें जानकारी

एएसपी ने कहा कि पुलिस व्दारा मांगे जाने पर डेली सेंटलमेंट रिपोर्ट तथा बेनीफेसरी डिटेल तत्काल उपलब्ध कराया जाए। बैंक शाखाओं में किसी भी ग्राहक के बैंक का खाता किसी भी बैंक व्दारा होल्ड लगाने पर इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। साइबर ठगी के अपराधों (सेक्सटार्सन, डिजीटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग आदि) से पीड़ित व्यक्ति के बैंक आने पर उसकी हरसंभव सहयोग किया जाए। पुलिस व्दारा फाईनेंसियल व एटीएम ठगी के प्रकरणों में ठगों के खातों में ट्रांसफर रकम को तत्काल होल्ड करने सहित बैंकों में ठगों के खातों की राशि, होल्ड राशि को पीड़ितों के खाते में बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से वापस किया जाए।

संदिग्ध खातों की पहचान कर पुलिस को बताएं

संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को दी जाए। बैंक की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा बैंक के अंदर, बाहर के साथ ही बैंक के चारों दिशाओं में एवं मार्ग को कव्हर करते हुये लगाया जाए। कैमरा लगातार चालू रखा जाए। बैकअप डाटा रखा जाए । बैंक का आलर्म सुचारू रूप से कार्य करें, इस हेतु समय-समय पर इसे चेक किया जाए। सभी बैंकों में गार्ड रखा जाए एवं गार्ड के आर्म्स का वेरिफिकेशन कराया जाए। बैंक में फायर सिस्टम लगाया जाए। संदिग्धों की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए।

बैंक व पुलिस के बीच बनी सहमति

बैंक प्रबंधकों को अपने बैंक के वाट्सएप ग्रुप के साथ संबंधित थाना व चौकी के अधिकारी व कर्मचारी को जोड़ने या थाना व चौकी के अधिकारी व कर्मचारी के वाट्एप ग्रुप में बैंक के अधिकारी व कर्मचारी को जोड़ने, संदिग्ध एकाउण्ट की जानकारी पुलिस को देने हेतु आवश्यक सहमति बनी। साथ ही बैंकों के टेक्नीकल स्टाफ एवं पुलिस के साईबर सेल के मध्य समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाने हेतु आने वाले समय में एक सेमीनार का आयोजन किये जाने के संबंध में विचार किया गया। बैठक में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी हरिश पाटिल, डीएसपी हेम प्रकाश नायक सहित 75 से अधिक बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

पत्नी के बार-बार आत्महत्या करने के प्रयास व धमकी को अब हाईकोर्ट ने माना क्रूरता

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा आत्महत्या करने की बार-बार धमकी देने और प्रयास करने को क्रूरता माना है। इस आधार पर पति को तलाक की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी जीवनसाथी शांति से नहीं रह सकता। पति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पत्नी बार-बार आत्महत्या की धमकी देती थी।

दुर्ग जिला निवासी याचिकाकर्ता युवक की 28 दिसंबर 2015 को बालोद निवासी युवती के साथ चर्च में शादी हुई। पत्नी शादी के बाद निजी कॉलेज में जॉब करने लगी। उसे 22 हजार रुपये वेतन मिलता था, इसमें से 10 हजार रुपये अपने माता-पिता को भेजती थी। पति ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। पत्नी ने कुछ दिन अपने भाई को भी

साथ रखा। भाई किसी कारण से वापस चला गया। इसके बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। बात-बात में वह आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी। कभी नशीला सिरप पीया तो कभी छत से कूदी।

पहली बार उसने रसोई में घुस कर दरवाजा बंद कर गैस चालू कर जल मरने की धमकी दी। दूसरी बार अत्यधिक मात्रा में नशीला कफ सिरफ पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद एक बार उसने छत से कूद कर आत्महत्या का प्रयास किया। इस पर पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया। न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। वहीं पत्नी ने भी वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए याचिका प्रस्तुत की। दोनों की याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे एवं संजय कुमार जायसवाल की डीबी में सुनवाई हुई।

सुनवाई उपरांत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता के समान है।साथ ही अगर यह आशंका पैदा हो जाए कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उसके लिए हानिकारक होगा तो साथ रहना मुश्किल है। फरवरी 2018 से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। पत्नी के आचरण को देखते हुए मानसिक दबाव में पति का उसके साथ रहना सम्भव नहीं है। कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर पति के तलाक की याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट ने पति को दो माह के अंदर पत्नी को 5 लाख रुपए स्थाई गुजारा भत्ता एक मुश्त देने का निर्देश भी दिया है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के साथ ही धान के अवैध परिवहन व भंडारण पर हो रही कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी के साथ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ धान के कोचियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि मंडी खाद्य और राजस्व विभाग की टीम सतत निगरानी कर रही है। अब तक अवैध धान के 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 563.20 क्विंटल धान अब तक जब्त हो चुका है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

ग्राम डढारी के सुरेश कुमार साहू से 40 क्विंटल धान, ग्राम कुसुमकसा के कृपाराम सिन्हा से 36.80 क्विंटल धान, ग्राम गुजरा के नरेश कुमार भुआर्य से 31.20 क्विंटल धान, ग्राम मड़ियाकट्टा के

पुरानिक राम सोरी से 24 क्विंटल धान कुल 04 प्रकरण अंतर्गत 132 क्विंटल धान जप्ती की कार्यवाही की गई है और कार्यवाही की है प्रक्रिया लगातार चल रही है यह कुछ मामले हैं जिसका जिक्र हमने किया है और भी इससे जुड़े हुए मामले हैं।

जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने बताया कि अपने पजीकृत रकबे में संपूर्ण धान का विक्रय करने वाले किसान उत्पादित धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर करने के बाद यदि कुछ रकबा शेष बच रहा है। उसे समर्पण करते हुए शेष रकबे को लॉक करवा लें। जिससे उनके शेष रकबे पर फर्जी खरीदी या कोई भी कोचिया या व्यापारी अपना धान विक्रय न कर सके।

दुपहिया वाहन चोर ने रेकी कर चालाकी से किया एक्टिवा पार

रायपुर। राजधानी रायपुर में दुपहिया वाहन चोरी करने वाले एक चोर का विडियों वायरल हो रहा है जिसमें चोरी पहले कुछ देर रेकी करता है फिर वाहन पर बैठकर बड़ी आसानी से वाहन में चाबी लगाकर वाहन लेकर चला जाता है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार डॉ आकाश पटेल ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसने अपनी एक्टिवा वाहन शर्मा अपार्टमेंट के बाहर साईं नगर रायपुर में खड़ा कर दिया था। 23 नवंबर को जब वह गाड़ी को चलाने के लिए देखा गाड़ी वहां पर खड़ी नहीं थी। आसपास तलाश करने पर भी गाड़ी नहीं मिली। जिसके बाद पूरा मामला पुलिस थाने पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने घटना क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों को खंगाला तो एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि दोपहर के वक्त एक्टिवा में एक युवक आकर बैठता है। उसने एक हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है। वह गाड़ी में पोज मार कर बैठता है और मोबाइल में बात करने की एक्टिंग करता है और दूसरे हाथ से मास्टर की के सहारे डिक्की खोल रहा है। कुछ देर कोशिश करने के बाद डिक्की खुल गई। तो चोर ने पहले तो उठाईगिरी करने के लिए अंदर नगद या कीमती सामान की तलाश की और उसके बाद चाबी को गाड़ी में लगाकर वह मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस सीसीटीव्ही के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।

तंत्र-मंत्र से पैसों की बारिश कराने के नाम पर 52 लाख की ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। तंत्र-मंत्र से पैसों की बारिश कराने के नाम पर मथुरा के रहने वाले तीन आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से 52 लाख 49 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। एसपी मणिशंकर चंद्र ने बताया कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

परसवानी गांव के रहने वाले लेखराम चंद्राकर को धरमपाल गुप्ता और रेखा राजपूत ने बताया कि मथुरा निवासी मोहन शर्मा तंत्र-मंत्र की विद्या से लोगों के दुख तकलीफ दूर करते हैं और पैसों की बारिश करवाते हैं। आरोपियों ने पीडित को तंत्र-मंत्र का फोटो, वीडियो, पैसों की गड्डी की फोटो, तंत्र-मंत्र क्रियाओं की तस्वीर वाट्सअप में भेजी थी। लेखराम उनके झांसे में आ गया। पीडित ने ऑनलाइन माध्यम से बाबा और दो चेले के खाते यानी कि तीनों के खातों में 18 अक्टूबर 2021 से 25 दिसंबर 2023 तक कुल 52 लाख 49 हजार 425 रुपए दिए। जब तीनों की कही गई बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखी और पैसों की बारिश नहीं हुई तो पीडित ने थाने में मामला दर्ज करवाया।

शादीशुदा महिला से अवैध संबंध, पकड़ाने पर हुई सामाजिक बैठक लगाया दो लाख का जुर्माना, परेशान होकर युवक ने की खुदकुशी

मरने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में समाज की ओर लगाए गए भारी-भरकम जुर्माना से आहत एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उसने रकम वापसी की गुहार लगाई थी। कोई सुनवाई नहीं होने के बाद युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जशपुर जिला के सन्ना थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां के गाड़ाकोना में रहने वाले यादव समाज के युवक का प्रेम-प्रसंग एक शादीशुदा महिला के साथ चल रहा था। समाज के लोगों को जब इस प्रेम प्रसंग की भनक लगने पर

बैठक बुलाया गया। बैठक में समाज के प्रमुख लोगों ने इस तरह के अवैध संबंध पर कड़ी आपत्ति जताते हुए युवक पर दो लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया। बताया जा रहा है कि समाज के इस फैसले के बाद युवक काफी परेशान था। समाज के इस फैसले के बाद किसी तरह युवक ने शादीशुदा महिला को दो लाख रुपये दिये थे। सरपंच सचिव के दबाव में आकर उसने महिला को और भी पैसे दिये थे।

इसके बाद मानसिक रूप से परेशान युवक ने अपनी रकम वापसी को लेकर फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। समाज के द्वारा रकम वापसी को लेकर कोई पहल नहीं किया गया। जिससे निराश होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। फेसबुक पोस्ट में मृतक श्रवण कुमार ने गांव के सरपंच-सचिव सहित अन्य प्रमुख लोगों पर लगाया है। घटना की जानकारी के बाद अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फेसबुक पेज पर मृतक ने जरूर अपने पैसे वापस लौटाने की बात लिखी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

जशपुर एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच में पता चला है कि मृतक का शादीशुदा महिला के साथ संबंध को लेकर गांव के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद मृतक से समाज के प्रमुख लोगों के दबाव में महिला और उसके पति को चेक के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये और 50 हजार रुपये कैश दिये थे। इसके बाद भी युवक पर 5 लाख रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा था। एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि साामजिक बैठक में किसी पर जुर्माने की कार्रवाई करना गैर कानूनी है। मामले की जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जायेगी।

प्रधानपाठक ने बीइओ को पीटा, अपराध दर्ज

अभनपुर। अभनपुर बीईओ कार्यालय में ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी धनेश्वरी साहू को परसदा स्कूल के प्रधान पाठक राजेंद्र बघेल द्वारा कुटाई कर दिया गया । बताया गया कि राजेंद्र बघेल की सेवा पुस्तिका में उनका सीआर (क) से (ख) कर देने की बात सामने आई है जिस पर राजेंद्र बघेल ने धनेश्वरी साहू अभनपुर के कार्यालय में पहुंचकर उनसे इस कृत्य का विरोध करते हुए सुधार करने की बात कही जिस पर धनेश्वरी साहू ने क्रोध में आकर उनकी फाइल और सेवा पुस्तिका को उन्हीं के ऊपर में पटक दिया। जिसमें राजन बघेल ने टेबल में पटक कर धनेश्वरी साहू को घूसा घूसा मारा इस दौरान कार्यालय के बहुत सारे कर्मचारी शिक्षक भी मौजूद थे। इस पर धनेश्वरी साहू ने पुलिस थाना अभनपुर में राजन बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा उनको निलंबित भी कर दिया गया है । देखा जाए तो अभनपुर शिक्षा विभाग का प्रमुख कार्यालय जहां पर ब्लॉक के सभी शिक्षकों का वेतन आहरित होता है छुट्टियां मंजूर होती हैं । जीपीएफ आदि के क्लेम निकाले जाते हैं इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग कभी कार्य रहता है जहां पर भ्रष्टाचार किए जाने के समाचार आते रहे हैं।

सीएम साय ने दी रायगढ़ को 137 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त भी जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। विकास कार्यों में सीएम साय ने रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक लाइब्रेरी नालंदा परिसर का भूमिपूजन किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री साय ने रायगढ़ में नालांदा परिसर का किया भूमिपूजन

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।

आज ही के दिन हुई थी विष्णु के सुशासन की शुरुआत : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

सीएम साय के नेतृत्व में रायगढ़ में हो रहा तेजी से विकास : ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी

रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया। नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24म7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

पीएससी टापर्स की आंखों में देखी भरोसे की चमक

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।

किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।

महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सास सहित घर की तीनों बहुएं ले रहीं महतारी वंदन योजना का लाभ

अपने निजी जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो रही राशि

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू होने से माताएं बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। महिलाएं चाहे वह कामकाजी हो अथवा गृहणी, वे सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती हैं और परिवार के स्वास्थ्य, दिनचर्या, बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतों इत्यादि को पूरा करने में समय और पैसा खर्च कर देतीं हैं।

अपने लिए तो कभी सोचतीं हीं नहीं हैं। ऐसी ही कहानी है धमतरी शहर से लगे ग्राम मुजगहन की कृष्णा सेन और उनकी तीनों बहुओं श्रीमती तरूण, श्रीमती पुष्पा और श्रीमती ममता का। वैसे तो सास सहित बहुएं कुछ न कुछ कार्य करती हैं और घर खर्च के लिए अपने-अपने पति का हाथ बटातीं हैं, लेकिन स्वयं के लिए कभी भी खर्च नहीं कर पातीं।

सास कृष्णा बाई बतातीं हैं कि उनके पति पवन कुमार सेन सेलून का कार्य किया करते थे, लेकिन

अधिक उम्र और बेटों का इस काम में हाथ बटाने के कारण अब नहीं करते हैं। उनके बेटे सेलून का काम करते है।

बहुए क्रमशः तरूण, पुष्पा और ममता भी घरेलू काम के साथ अन्य कार्य करती है। अपने परिवार और बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य जरूरतों में खर्च करते हैं। वे बतातीं हैं शासन द्वारा मिल रही महतारी वंदन योजना की राशि को अब वे अपने निजी जरूरतों को पूरा करने में खर्च करतीं हैं। उन्होंने कहा कि जब भी अपने लिए खर्च के बारे में सोचो, परिवार और बच्चों की जरूरतें ख्याल में आ जातें थे, लेकिन अब वे निश्चिंत होकर अपने लिए खर्च करने के बारे में सोचतीं हैं और काफी खुश रहतीं हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व में दिव्यांग व्यक्तियों को मिल रहा है कई योजनाओं का लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

एमसीबी। विश्व दिव्यांग दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उनके लिए अवसरों का विस्तार करना और उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिव्यांग दिवस की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक ऐसा समाज बनाना जहां वे बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, इस दिव्यांग दिवस का मुख्य लक्ष्य है।

सन् 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने ''अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष'' मनाया। इसके बाद 1983 से 1992 के दशक को ''दिव्यांग व्यक्तियों का दशक'' घोषित किया गया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गए। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) लागू किया। यह अभिसमय दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के हर क्षेत्र में अधिकार और समावेश प्रदान करने के लिए कानूनी मान्यता देता है। भारत ने इसे 2007 में अंगीकृत किया और इसे अपनी नीतियों में सम्मिलित किया। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर 1995 में ''दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम'' लागू हुआ। इस अधिनियम ने शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। 2016 में इस कानून को संशोधित कर दिव्यांगताओं की संख्या 21 कर दी गई और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाया गया है। केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ''सुगम्य भारत अभियान'' प्रमुख है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक भवनों, परिवहन और डिजिटल सेवाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना है। ''दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग'' दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। वहीं ''स्किल इंडिया'' पहल के अंतर्गत दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिव्यांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। समावेशी शिक्षा के तहत विशेष स्कूल और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ''सुगम छत्तीसगढ़ अभियान'' के माध्यम से सार्वजनिक भवनों और परिवहन को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल बनाया गया है। सरकार ने विभिन्न प्रकार के निःशुल्क उपकरण वितरण और दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक और भौतिक सहायता प्रदान की है। फिर भी आज दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। इनमें समाज में भेदभाव, सुविधाओं की कमी और रोजगार और शिक्षा में सीमित अवसर प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्कूल खोलने और तकनीकी नवाचार का उपयोग करने की आवश्यकता है।

आज दिव्यांगता को शारीरिक, मानसिक, संवेदी और बौद्धिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक दिव्यांगता जैसे पोलियो या रीढ़ की हड्डी में चोट, दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित दिव्यांगता, मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता और न्यूरोलॉजिकल दिव्यांगता मुख्य प्रकार हैं। इनके प्रमुख कारणों में जन्मजात दोष, दुर्घटनाएं, संक्रमण, कुपोषण और मानसिक आघात शामिल हैं। इन समस्याओं का उपचार फिजियोथेरेपी, सर्जरी, काउंसलिंग और सहायक उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी उन्हें कहीं-कहीं भेदभाव का शिकार बनाया जाता है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उनके अवसर सीमित होते हैं, और सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों की कमी भी उनकी चुनौतियों को बढ़ाती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, सुलभता बढ़ाने, विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है।

केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें ''सुगम्य भारत अभियान'', ''दिव्यांगजन स्वरोजगार योजनाएं'' और ''कृत्रिम अंग योजनाएं'' प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में समावेशी शिक्षा, स्वरोजगार योजना और ''सुगम छत्तीसगढ़ अभियान'' जैसी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह विश्व दिव्यांग दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह दिव्यांग दिवस हमें एक ऐसा समाज बनाने की प्रेरणा देता है जो समानता, अधिकार और समावेशिता के मूल्यों पर आधारित हो। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन प्रयासों को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान और समान अवसर मिले।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950